ख़्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह पर ज़ियारत करने अजमेर आए जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नैशनल कॉन्फ्रेंस प्रमुख डॉ. फारुख अब्दुल्लाह का भावभीना स्वागत किया गया। इस अवसर पर क्षेत्र के कांग्रेस नेता महेन्द्र सिंह रलावता, कलैक्टर अंशदीप सिंह, एस.पी. चूनाराम जाट तथा दरगाह के खादिम सैयद फखरे मोईन भी मौजूद थे।

फारूख अब्दुल्लाह ख़्वाजा साहब की जियारत करने अजमेर आए

अजमेर, 11 फरवरी (कासं)। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूख अब्दुल्ला सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह जियारत करने के लिए एक दिवसीय यात्रा पर अजमेर पहुंचे। उन्होंने कहा है कि जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति और गृह मंत्रालय का कानून चल रहा है। गृह मंत्रालय को लगता है कि अमन शांति है तो चुनाव आयोग को वहां चुनाव कराना चाहिए। उनकी पार्टी तो लंबे समय से चुनाव कराने की मांग कर रही है। यह किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि जम्मू कश्मीर के हालात कैसे हैं। अगर कानून व्यवस्था ठीक है तो कश्मीरी पंडित जम्मू में रहने को क्यों मजबूर हैं। कश्मीरी पंडितों को जम्मू में न रोजगार मिल रहा है और न ही वेतन, उनके भूखे मरने की हालत हो गई है।

फारूख अब्दुल्ला ने एक सवाल के जवाब में कहा कि कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने जो भारत जोड़ो यात्रा निकाली वह पूरी तरह कामयाब रही है, देश में हिंदू, मुस्लिम, सिक्ख, इसाई को अलग कर भारत को बांटने का काम हो रहा है, जबकि सभी सब मिलकर ही एक भारत बनाते हैं। भारत एक बाग है, जहां हर तरह की कली है। एक कली मर जाएगी तो बाग की खूबसूरती खत्म हो जाएगी। उन्होंने

- **अजमेर दौरे पर उन्होंने पत्रकारों द्वारा जम्मू-कश्मीर पर पूछे गये सवालों के भी जवाब दिए।**
- **उन्होंने कहा, अगर कश्मीर में अमन चैन है, जैसा गृह मंत्रालय का दावा है, तो चुनाव आयोग को वहां चुनाव करवाना चाहिए।**
- **उन्होंने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को कामयाब बताते हुए कहा कि, सभी धर्म मिलजुल कर रहें यही देश की खूबसूरती है।**

धर्म के लोग एक साथ रहें, यही देश की खूबसूरती है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री स्वयं कहते हैं कि दुनिया छोटी हो गई है, अगर ऐसा है तो सभी मुल्कों को मिल कर रहना चाहिए। अब्दुल्ला ने कहा कि तमिलनाडू और कश्मीर में कोई समानता नहीं, लेकिन देश की ओर से तुर्की को भेजी गई मदद की भी सराहना की। उन्होंने कहा कि भारत से भेजी गई मदद से हजारों लोगों की जान बचाई है। विश्व में भारत की साख बनाने की जो परंपरा शुरू हुई वह इंदिरा गांधी की समय में हुई, इस समय हालत यह है कि सार्क की बैठक नहीं हो रही है। जम्मू में विधानसभा क्षेत्रों के परिसीमन से सम्बंधित सवाल का जवाब देते हुए अब्दुल्ला ने कहा कि यह गलत हुआ है, पूरे देश में परिसीमन 2026 में होना है, उसी समय पर जम्मू कश्मीर का भी कराना चाहिए था। उन्होंने कहा कि केंद्र ने एक नया मुद्दा छेड़ दिया है। जम्मू कश्मीर में अपने चहेतों को नियुक्त किया जा रहा है। दावा यह है कि वह छह महीने तक रहेंगे, लेकिन सच्चाई यह है कि अगर दस साल तक चुनाव नहीं होते तो वे तब तक वहीं रहेंगे।

उन्होंने नए केन्द्रीय बजट को चुनावी बजट करार दिया और वित्त मंत्री को सलाह दी कि पिछले बजट की समीक्षा करें। जम्मू कश्मीर को मिले बजट का महज 40 फीसदी ही खर्च हुआ है। इस अवसर पर उनका कांग्रेस नेता महेंद्र सिंह रलावता, एसपी चूनाराम जाट, कलेक्टर डॉ. अंशदीप, दरगाह के खादिम सैयद फखरे मोईन आदि ने स्वागत किया।

प्रदेश प्रभारी रंधावा के बयान तो खूब आ रहे हैं,पर असर नहीं छोड़ पा रहे?

जयपुर, 11 जनवरी (का.प्र.)। राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट के बीच तनाव नया नहीं है। इन दोनों के बीच अंतर्द्वंद के चलते राजस्थान से अब तक दो प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे और अजय माकन राजस्थान से जा चुके हैं और अब नए प्रभारी के रूप में सुखजिंदर सिंह रंधावा आए हैं। अविनाश पांडे जहां एक पक्षीय व्यवहार के चलते राजस्थान से हटाए गए थे, तो दूसरी ओर अजय माकन ने राजस्थान में अनुशासनहीनता पर कार्यवाही नहीं होने के चलते खुद पद छोड़ दिया था।

अब राजस्थान में चुनावी वर्ष चल रहा है। ऐसे में रंधावा के लिए जल्द से जल्द इन दोनों नेताओं के बीच सुलह कराना आवश्यक है, अन्यथा जैसे - जैसे चुनावी समय नजदीक आएगा, वैसे-वैसे दोनों खेमों के बीच टकराव और बढ़ेगा। राजस्थान का प्रभारी बनने के बाद में सुखजिंदर सिंह रंधावा प्रदेश के दौरे तो लगातार कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कहीं भी ऐसा नजर नहीं आया है कि वह दोनों नेताओं के बीच के मतभेद समाप्त करवाने के आस-पास भी पहुंचे हैं। हाल ही शुरू हुए हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम में भी दोनों खेमों के बीच टकराव की वजह से भारी गुटबाजी देखी जा रही है। यही नहीं जहां खुद रंधावा मौजूद थे। वहां भी गुटबाजी का नज़ारा देखा गया। कहा जा रहा है कि जब रंधावा जिला स्तर पर गुटबाजी रोकने में असफल नजर आ रहे हैं, तो गहलोत -पायलट तनाव कैसे दूर कर पाएंगे।

हालांकि रंधावा दोनों पायलट-गहलोत के बीच टकराव की बात से हमेशा इनकार करते हैं। लेकिन पायलट ने 5 जिलों की यात्रा में पेपर लीक और नौकरशाही को लेकर सरकार पर निशाना साधा तो मुख्यमंत्री गहलोत ने भी पायलट का नाम लिए बिना उन पर तीखी बयानबाजी की। पिछले दिनों अजमेर, कोटा और अलवर में हुए हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम में खुद प्रभारी रंधावा पहुंचे थे, लेकिन अजमेर को छोड़ दें, तो कोटा और अलवर में सचिन पायलट समर्थकों को कार्यक्रमों में बुलाया तक नहीं गया। कोटा में तो राजनीतिक नियुक्तियां पा चुके प्रदेश कांग्रेस के पूर्व सदस्यों को भी संभाग स्तरीय कार्यक्रम में नहीं बुलाया गया। स्पष्ट है कि यह गुटबाजी कम तो नहीं हो रही है। एक दिन पहले ही प्रभारी रंधावा ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को बड़ा भाई तो सचिन पायलट को छोटा भाई बताया और दोनों के बीच किसी भी तरह की तकरार से भी इनकार किया है, लेकिन इस तरह से अंतर्द्वंद समाप्त नहीं हो सकता, यह सभी जानते हैं। गौरतलब है कि जयपुर में हाथ से हाथ जोड़ो अभियान की तैयारी बैठक के समय प्रभारी के रूप में रंधावा के भाषण इस तरह के थे कि वे बहुत सख्ती से पेश आएंगे लेकिन बयानों के उलट रंधावा कुछ भी करने की स्थिति में फिलहाल नजर नहीं आए हैं। हालात तो यह है कि जब वे जयपुर आए तो एयरपोर्ट पर उन्हें लेने के लिए कोई विधायक या मंत्री तक नहीं पहुंचा। वही उनकी मौजूदगी में हो रहे संभाग स्तरीय कार्यक्रमों में भी कोई प्रभावी उपस्थिति या नहीं हो रही है।

- **उनको गहलोत और पायलट का झगड़ा समाप्त करने का टास्क दिया गया है, लेकिन उनकी मौजूदगी में संभाग स्तरीय कार्यक्रमों में ही गुटबाजी पनप रही, तो बड़ा झगड़ा कैसे निपटाएंगे।**
- **रंधावा के कहने के बावजूद ना तो प्रदेश कांग्रेस का विस्तार हो पा रहा है, ना ब्लॉक अध्यक्ष ही पूरे बन पाए हैं, जिला अध्यक्ष कब तक बन पाएंगे, यह कहना भी मुश्किल है।**

प्रदेश कांग्रेस में गुटबाजी इस कदर है कि 400 ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष बनाने के लिए अभी तक 5 सूचियां जारी हो चुकी हैं, फिर भी बहुत से ब्लॉक अध्यक्ष पद अभी भी खाली हैं। वही मंडल अध्यक्षों की सूचियां तो आधी भी जारी नहीं हो पाई हैं। सवाल है कि जब वे ब्लॉक और मंडल बनाने में कामयाब नहीं हो पा रहे हैं, तो फिर जिला कांग्रेस अध्यक्षों का मामला किस तरह से सुलझा पाएंगे। कांग्रेसजनों का कहना है कि रंधावा मिलते तो सबसे हैं। चर्चा भी करते हैं, लेकिन जितना आश्वासन देते हैं, उस हिसाब से अभी तक पार्टी को संदेश देने में सफल नहीं हो पाए हैं।

अब 12 घंटे में ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

है। प्रधानमंत्री नैशनल हाइवे प्रोजैक्ट्स के 247 कि.मी. की भी आधारशिला रखेंगे। इसे 5 हजार 940 करोड़ रूपयों की लागत से विकसित किया जाएगा।

एक्सप्रेस वे से दिल्ली और मुम्बई के बीच की दूरी 1 हजार 424 कि.मी. से घटकर 1 हजार 242 कि.मी. यानी की 12 प्रतिशत घट जाएगी। और यात्रा समय भी 24 घंटे से आधा कम होकर 12 घंटे का हो जाएगा। इस एक्सप्रेस वे में 12 हजार 150 करोड़ की लागत से बनाए गए 246 कि.मी. लम्बे दिल्ली-दौसा-लालसोट भाग से दिल्ली-जयपुर की यात्रा का समय 5 घंटे से कम होकर लगभग 3.5 घंटे हो जाएगा। दिल्ली-मुम्बई एक्सप्रेस वे एक महत्वकांक्षी इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजैक्ट है, जिसका दिल्ली-दौसा-लालसोट प्रथम भाग निर्मित हो चुका है और प्रधानमंत्री इसका रविवार को उद्घाटन करेंगे। आठ लेन एवं एक्सैस कन्ट्रोल्ड वाले दिल्ली-मुम्बई ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस वे का अन्ततः 12 लेन्स में विस्तार होगा। यह एक्सप्रेस वे कोटा, जयपुर, इंदौर, भोपाल, बड़ोदरा और सूरत जैसे महत्वपूर्ण शहरों को जोड़ते हुए हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, दिल्ली, गुजरात और महाराष्ट्र से होकर गुजरेगा।

विश्व हिन्दी सम्मेलन फिज़ी में 15 से

नयी दिल्ली, 11 फरवरी। फिजी में 15 से 17 फरवरी तक होने वाले विश्व हिन्दी सम्मेलन में 270 सदस्यीय भारतीय दल शामिल होगा। फिजी सरकार के साथ भारत के विदेश मंत्रालय के समन्वय से इस सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है।

एक उच्च स्तरीय अधिकारी ने शनिवार को यहां बताया कि, विदेश मंत्री एस. जयशंकर और फिजी के प्रधानमंत्री सितीवेनी राबुका संयुक्त रूप से इस सम्मेलन का फिजी के नादी स्थित देनाराउ द्वीप सम्मेलन केन्द्र में उद्घाटन करेंगे। पिछले वर्ष दिसंबर के अंत में फिजी में नयी सरकार के गठन के बाद भारतीय विदेश मंत्री का यह पहला उच्च स्तरीय दौरा होगा। फिजी के उप प्रधानमंत्री बिमान प्रसाद इस सम्मेलन के 17 फरवरी को होने वाले समापन समारोह में शामिल होंगे। प्रसाद ने इस सप्ताह की शुरुआत में भारत का दौरा किया था। उन्होंने इस दौरान जयशंकर और अन्य अधिकारियों से मुलाकात की थी। विदेश मंत्रालय के सचिव (पूर्व) सौरभ कुमार ने बताया कि फिजी में विश्व हिन्दी सम्मेलन आयोजित करने का निर्णय वर्ष 2018 में मॉरीशस में हुए विश्व हिन्दी सम्मेलन में लिया गया था। विदेश राज्य मंत्री वी. मुरलीधरन और गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा भी इस सम्मेलन में शामिल होंगे। सौरभ कुमार ने बताया कि, गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग ने इस सम्मेलन को आयोजित करने में मदद की है।

- **विदेश मंत्री एस. जयशंकर और फिज़ी के प्रधानमंत्री सितीवेनी राबुका संयुक्त रूप से इस सम्मेलन का फिजी के नादी स्थित देनाराउ द्वीप सम्मेलन केन्द्र में उद्घाटन करेंगे।**

अडानी ग्रुप ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

के गलत निवेश को अनुमति दे दी जाये कि वह पोर्ट जैसे सामरिक महत्व के क्षेत्र पर अपना आधिपत्य स्थापित कर ले।

कांग्रेस नेता ने कहा कि जैसा एयरपोर्ट्स के मामले में हुआ है, आपकी सरकार ने पोर्ट-सैक्टर में भी अडानी के एकाधिकार को सुगम बना दिया है तथा अडानी ग्रुप सारे संसाधनों को अपने लिये और अपने तरीके से इस्तेमाल कर रहा है।

उन्होंने मोदी पर अपने चहेतों को खुश करने का आरोप लगाते हुये कहा कि सरकार ने बिना किसी नीलामी के विभिन्न पोर्ट अडानी ग्रुप को रियायती दर पर बेच दिये हैं।

रमेश ने कहा कि आश्चर्य की बात तो यह है कि जहाँ नीलामी कराई गई, वहाँ प्रतिस्पर्धी कंपनियाँ नीलामी से आश्चर्यजनक रूप से गायब रहीं। उन्होंने कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि इनकम टैक्स के छापों में कृष्णापटनम पोर्ट के पूर्व मालिक को यह समझाने में मदद की कि वह इस पोर्ट को अडानी ग्रुप को बेच दे।

जयराम रमेश ने पूछा कि क्या यह सही है कि 2021 में, सार्वजनिक क्षेत्र का जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट महाराष्ट्र डिप्पी पोर्ट के लिये अडानी की प्रतिस्पर्द्धा में नीलामी की बोली लगा रहा था लेकिन उसे अपनी विनिंग बिड को वापस लेने के लिये बाध्य कर दिया गया क्योंकि जहाजरानी तथा वित्त मंत्रालयों ने उसकी विड के समर्थन के बारे में उसका विचार ही बदल दिया था।

रमेश ने कहा कि सामान्यतः "स्पेशल परपज़ वीकल्स" प्रत्येक पोर्ट के संबंध में जोखिमों को दूर करने तथा सम्पत्तियों के बचाव के लिये, रियायतों को लेकर मोल-तोल किया करता है लेकिन फिर भी, इनमें से बहुत से पोर्ट इस समय केवल एक कंपनी- अडानी पोर्ट्स तथा सेज़ का हिस्सा हैं। उन्होंने पूछा कि क्या परिसम्पत्तियों के इस हस्तान्तरण में "मॉडल कन्सेशन एग्रीमैन्ट फॉर पोर्ट्स" का उल्लंघन किया गया है? क्या कन्सेशन एग्रीमैन्ट अडानी के वाणिज्यिक हितों के अनुरूप बदले गये हैं?

प्रश्नों का यह सैट प्रश्नों की श्रृंखला का सातवाँ सैट है तथा इसे शीर्षक दिया गया है- "हम अडानी के हैं कौन (एच.ए.एच.के.)।"

चूँकि, अडानी मुद्दे को लेकर मोदी पूरी तरह खामोशी धारण किये हुये हैं तथा ध्यान रख रहे हैं कि उनके मुँह से एक भी शब्द नहीं निकले, इसलिये कांग्रेस इन प्रश्नों को पूछकर, इस मुद्दे को जीवित बनाये रखने की कोशिश कर रही है।

यू.पी. के 30 शहरों में होटल खोलेगा जापान का एच.एम.आई. ग्रुप

लखनऊ, 11 फरवरी। जापान के प्रसिद्ध होटल समूह होटल मैनेजमेंट इंटरनेशनल कम्पनी लिमिटेड (एच.एम.आई.) ने उत्तर प्रदेश में 30 नये होटल बनाने का ऐलान किया है।

लखनऊ में चल रहे ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट (जी.आई.सी.) के दूसरे दिन शनिवार को जापानी कंपनी ने प्रदेश सरकार के साथ इस संबंध में 7200 करोड़ रूपये के निवेश का समझौता किया। जापान के प्रमुख शहरों में 60 से अधिक होटल संचालित कर रहे एच.एम.आई. ग्रुप के निदेशक, पब्लिक रिलेशन टाकामोटो योकोयामा ने कहा कि, उत्तर प्रदेश में पर्यटन की अपार संभावनाओं के मद्देनजर उनकी कंपनी ने यहां होटल व्यवसाय में उतरने का फैसला किया है।

काशीविश्वनाथ धाम कॉरीडोर के विकास के बाद वाराणसी में बड़ी संख्या में पर्यटक आ रहे हैं, यह हमारे लिए अनुकूल अवसर है। यूपी की औद्योगिक नीतियां एच.एम.आई. समूह को प्रोत्साहित करने वाली हैं। ऐसे में एच.एम.आई. समूह आगरा, वाराणसी और अयोध्या सहित 30 प्रमुख स्थानों पर अपने होटल चेन का विस्तार करेगी। इससे यहां के 10 हजार से अधिक लोगों के लिए नौकरी के प्रत्यक्ष मौके भी बनेंगे। इससे पहले, दधीचि सभागार में उत्तर प्रदेश में जापान और भारत के बीच विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी का क्रियान्वयन विषयक महत्वपूर्ण सत्र में विदेश मंत्रालय, भारत सरकार में सलाहकार (जापान) प्रो. अशोक चावला ने वर्ष 2000 से 2014 और 2014 से 2022 के अलग-अलग कालखंड में भारत और जापान के राजनीतिक, रणनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक संबंधों की तुलनात्मक चर्चा की। उन्होंने कहा कि, वर्ष 2015 में तत्कालीन जापानी प्रधानमंत्री शिंजो आबे का भारत दौरा हुआ तो 2016 में प्रधानमंत्री मोदी जापान गए। वर्ष 2017 में शिंजो आबे अहमदाबाद आए और हाईस्पीड रेल के बारे में कार्ययोजना बनी तो 2018 में प्रधानमंत्री मोदी पुनः जापान गए। लगातार होने वाले इन शीर्ष नेताओं के दौरे से दोनों देशों के बीच गहरा विश्वास पैदा हुआ है।

- **लखनऊ में चल रहे ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट (जी.आई.सी.) के दूसरे दिन शनिवार को जापानी कंपनी ने प्रदेश सरकार के साथ इस संबंध में 7200 करोड़ रूपये के निवेश का समझौता किया।**

कांग्रेस महाधिवेशन ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

सदस्यीय सब-ग्रुप की अध्यक्षता करेंगे, जबकि पार्टी सांसद शशि थरूर इसके संयोजक होंगे। कृषकों और कृषि को लेकर बनाए गए 16 सदस्यीय सब-ग्रुप की अध्यक्षता हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री को सौंपी गई है। डॉ. रघुवीरा इसके संयोजक होंगे। सीनियर एडवोकेट विवेक तनखा सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण पर बने सब-ग्रुप की अध्यक्षता करेंगे। छठा ग्रुप युवा सशक्तिकरण और रोजगार को लेकर बनाया गया है।

आठ वर्षीया बालिका छह दिन बाद भूकंप के मलबे में जीवित मिली

नयी दिल्ली, 11 फरवरी। भारत के राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (एन.डी.आर.एफ.) की टीम ने तुर्की सेना के सहयोग से भूकंप प्रभावित क्षेत्र गाजियांटेप से आठ साल की एक बालिका को बचा लिया है। एन.डी.आर.एफ. ने शनिवार को यह जानकारी दी।

एन.डी.आर.एफ. ने ट्वीट किया कि, उनकी टीम ने कड़ी मेहनत से तुर्की सेना के साथ मिलकर एक और भूकंप पीड़ित को सुरक्षित बचाया है। आठ साल की बच्ची को गाजियांटेप में क्षतिग्रस्त इमारत के मलबे से सुरक्षित बाहर निकाला है।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक ट्वीट किया, "इससे पहले, तुर्की में राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (एनडीआरएफ) की टीम ने गाजियांटेप शहर में क्षतिग्रस्त इमारतों के मलबे के नीचे दबी एक बालिका को बचाया था। मुझे एन.डी.आर.एफ. पर गर्व है।"

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शुक्रवार को कहा था, "एन.डी.आर.एफ. कर्मियों की भारतीय टीम और भूकंप प्रभावित तुर्की में बचाव और राहत कार्यों में शामिल डॉक्टर "ऑपरेशन दोस्त" के हिस्से के रूप में दिन-रात काम कर रहे हैं। भारत तुर्की के लोगों के साथ दृढ़ ता से खड़ा है।"

हिमाचल में भारी हिमपात हुआ

किन्नौर, चंबा और कुल्लू जिलों में पिछले 24 घंटों के दौरान तीन फीट तक बर्फ गिरी

शिमला, 11 फरवरी। हिमाचल प्रदेश के ऊंचे क्षेत्रों में हिमपात का क्रम जारी है। लाहौल स्पीति के केलांग मुख्यालय में रुक-रुक कर हिमपात हो रहा है।

लाहौल-स्पीति जिले के जोबरंग गांव में हिमस्खलन हुआ है, इससे किसी तरह के नुकसान की कोई सूचना नहीं है। शाम 4 बजे तक आठ सैन्टीमीटर तक हिमपात दर्ज हुआ है। ऊंचाई वाले क्षेत्रों व दर्रों में कल रात से लगातार हिमपात हो रहा है, जिससे समूचा जिला एक बार पुनः शीतलहर की चपेट में है।

वहीं, किन्नौर, चंबा और कुल्लू जिलों में पिछले 24 घंटों के दौरान भारी हिमपात हुआ है। प्रदेश में तीन नेशनल हाईवे समेत 216 सड़कें अवरुद्ध हैं। यह जानकारी राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के प्रवक्ता ने दी।

प्रवक्ता ने बतया कि, मनाली लेह नेशनल हाईवे, दारचा शिंकुला मार्ग और पांगी किलाड़ हाईवे 26 हिमस्खलन होने के कारण सभी प्रकार के वाहनों के लिए बंद हैं। काजा सड़क नेशनल हाईवे-505 ग्रांफू से काजा तथा समदो से लोसर भी सभी प्रकार के वाहनों के लिए बंद है। अटल टनल के साउथ पोर्टल, धुंधी में 37 सेंमी, सोलंगनाला में 25 सेंमी, पलचान में 20 सेंमी बर्फबारी रिकॉर्ड की गई। सुमित खिमटा ने सीमा सड़क संगठन के उच्च अधिकारियों को निर्देशित किया है कि मौसम की अनुकूलता पर मार्गों को जल्द बहाल किया जाए।

- **प्रदेश में तीन नेशनल हाईवे समेत 216 सड़कें अवरुद्ध हैं।**
- **अटल टनल के साउथ पोर्टल, धुंधी में 37 सेंमी, सोलंगनाला में 25 सेंमी, पलचान में 20 सेंमी बर्फबारी रिकॉर्ड की गई।**

महरौली में तोड़फोड़ रोकने के निर्देश

नयी दिल्ली, 11 फरवरी। दिल्ली के राजस्व मंत्री कैलाश गहलोत ने कहा कि नए सिरे से सीमांकन किए जाने तक महरौली में रह रहे निवासियों को विस्थापित नहीं किया जा सकता है।

उन्होंने विवादित क्षेत्र का नए सिरे से सीमांकन कराने का आदेश दिया है। राजस्व मंत्री ने कहा है कि कब्जाधारियों को बिना कोई नोटिस दिए अंधेरे में रखकर सीमांकन किया गया है। उन्होंने जिलाधिकारी (दक्षिण) को भूमि का नए सिरे से सीमांकन करने और डीडीए को तत्काल इस बारे में सूचित करने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि नए सिरे से सीमांकन किए जाने तक महरौली में रह रहे निवासियों को विस्थापित नहीं किया जा सकता है। उन्होंने इस मामले को लेकर संबंधित अधिकारियों की बैठक बुलायी। बैठक में सामने आया कि विभाग ने सीमांकन प्रक्रिया के दौरान उक्त व्यक्तियों को नोटिस जारी नहीं किया था।

केन्द्रीय योजनाओं...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

कि वह पुरानी योजनाओं को पुनः शुरू करने और उनका नाम बदलने में एक्सपर्ट हैं। हिमाचल प्रदेश में भाजपा एक विपरीत स्थिति में फंस गई है। बताया जाता है कि वहां की नई कांग्रेस सरकार ने अटल बिहारी वाजपेयी डे बोर्डिंग स्कूल्स का नाम बदलकर राजीव गांधी बोर्डिंग स्कूल्स कर दिया है।

करोलबाग स्थित पीएनबी में भीषण आग लगी

नयी दिल्ली, 11 फरवरी। राष्ट्रीय राजधानी के करोल बाग इलाके में पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) में शनिवार सुबह भीषण आग लग गई। दमकल सेवा के एक अधिकारी ने यह जानकारी दी।

अधिकारी ने बताया कि करोल बाग में गुरुद्वारा मार्ग पर स्थित पीएनबी में आज सुबह करीब 5 बजकर 15 मिनट पर भीषण आग लगने की सूचना मिली थी, जिसके तुरंत बाद उन्होंने कुल 17 दमकल गाड़ियों को घटनास्थल पर भेजा। उन्होंने बताया कि कड़ी मशक्कत के बाद सुबह करीब सात बजे आग पर काबू पा लिया गया। उन्होंने बताया कि अभी तक किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है।

- **सुबह करीब सवा पांच बजे लगी आग पर कड़ी मशक्कत के बाद सुबह सात बजे काबू पाया**

हिन्दुस्तान व वियतनाम में चल रही...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

कहा था कि भारत एक बड़ा रोमांचकारी बाजार है और कंपनी का यहां काफी फ़ोकस है। सी.एन.एन. के अनुसार कुक ने हाल ही कहा था कि "अगर भारत में हमारे कारोबार को देखें तो हमने वित्तीय तिमाही में लाभ का रिकॉर्ड बनाया है और पिछले एक वर्ष में डबल डिजिट ग्रोथ अर्जित की है। अतः अपने प्रदर्शन को लेकर हम अच्छा महसूस करते हैं।"

ऐपल के देश में हित को लेकर भारत सरकार आशान्वित हैं। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने हाल ही कहा था कि ऐपल अपने 5 से 7 प्रतिशत उत्पाद पहले ही भारत में बना रहा है। उन्होंने कहा कि "यदि मैं ग़लत नहीं हूं तो ऐपल का लक्ष्य भारत में 25 प्रतिशत उत्पादन तक का है।"

गोयल की टिप्पणी उस वक्त सामने आई है जबकि ऐपल का एक शीर्ष सप्लायर "फॉक्सकॉन" चीन में सप्लाई चेन में हुए व्यवधान से पीड़ित होकर भारत में अपने कार्यों का विस्तार करने पर विचार कर रहा है।

पिछले वर्ष के मध्य से लेकर अब तक ऐपल ने भारत में निवेश करने के प्रयास दोगुने कर दिए हैं, लेकिन मूल प्रश्न यह है कि क्या एशिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, भारत ऐपल को यहां काम करने लायक माहौल प्रदान कर सकेगी?

ऐसा क्या है जो भारत को इतना लाभप्रद बनाता है? दुनिया की सबसे अधिक आबादी के देश के रूप में भारत का इस वर्ष चीन से आगे निकलना तय है। भारत की विशाल एवं सस्ती श्रम शक्ति, जिसमें तकनीकी कौशल रखने वाले कामगार भी शामिल हैं, उत्पादनकर्ताओं के लिए एक बड़ा आकर्षण है। भारत में एक बढ़ता हुआ घरेलू बाजार भी है। बर्ष 2023, जिसमें वैश्विक मंदी का भय बना हुआ है, भारत के दुनिया में सबसे तेज बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में बने रहने की उम्मीद है। सैन्टर फॉर इकोनॉमिक्स एण्ड बिज़मैस रिसर्च के अनुसार यदि गति बनी रहती है, तो भारत वर्ष 2025 तक 10 ट्रिलियन डॉलर की जी.डी.पी. के साथ दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है।

विश्लेषकों का कहना है कि भारत का बढ़ता कंजूमर बेस उसे वियतनाम पर, जो कि इलैक्ट्रोनिकस मैन्युफैक्चरिंग बड़े निवेश आकर्षित करता रहा है, बढ़त दिला सकता है।

इसके अलावा ऐपल के कुछ सबसे बड़े ठेकेदार पहले से ही भारत में पूंजी लगा रहे हैं। गत वर्ष फॉक्सवॉन्व के घोषणा की थी कि वह भारत में अपनी सहायक कंपनी में एक अरब डॉलर का निवेश करेगा। इस सप्ताह के आरम्भ में कर्नाटक ने भी ताइवान की इस कंपनी के साथ निवेश योजनाओं पर गंभीर चर्चा की जानकारी दी थी। फॉक्सकॉन की आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में पहले से ही फैक्ट्रियां है।

लेकिन भारत में समस्याएं हैं। भारत में निर्माण में कई चुनौतियां है। वर्ल्ड बैंक के अनुसार यह भारत की जी.डी.पी. का मात्र 14 प्रतिशत है और सरकार इस आकंड़े को बढ़ाने के लिए जूझ रही है।

इन्फ्रास्ट्रक्चर की कमी के अलावा ऐपल जो भारत में चीन जैसे विशाल कारखाने बनाना चाहती है, को लाल फीताशाही का सामना भी करना पड़ेगा।

विशेषज्ञों का कहना है कि भारत जैसे अव्यवस्था से भरे लोकतांत्रिक देश में ज़मीन हासिल करना एक बड़ी चुनौती हो सकती है। वहीं चीन की सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी के लिए ज़मीन हासिल करना ज्यादा कठिन नहीं है। इसलिए भारत को ऐसी सरकारी नीतियां बनानी होगी ताकि आई फोन असैम्बल होने से आगे भी सोचा जा सके।

'संसद में मीडिया ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

आपातकाल में जब इंदिरा गांधी ने प्रैस-सैन्सरशिप लागू कर दी थी, तब भी संसद में पत्रकारों के प्रवेश पर रोक नहीं थी।

महामारी के आरम्भ में शुरु हुये प्रैस-गैलरी में प्रतिबंधित प्रवेश के मुद्दे को उठाने के अलावा, गिल्ड ने वरिष्ठ पत्रकारों को सैन्ट्रल हॉल में जाने के लिए दिए जाने वाले पास को निलम्बित कर दिये जाने के साथ ही, तीन साल से लोकसभा की प्रैस एडवाइजरी कमेटी गठित नहीं किये जाने का मुद्दा भी उठाया।

राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ को लिखे पत्र में गिल्ड ने कहा कि इस समय तो प्रतिबंध वापस ले ही लेना चाहिये, जब भारत अधिकतम वैक्सिनेशन के मामले में सबसे आगे बना हुआ है तथा खासतौर से ऐसे समय, जब हरेक क्षेत्र में, जीवन करीब-करीब सामान्य हो चला है।

राज्यसभा में बजट सत्र में प्रतिबंध फिर से लागू हो गया है, जबकि शीतकालीन सत्र में, इसमें कुछ ढ़ील दे दी गई थी, जिसके अन्तर्गत, एक पत्रकार को पाँच दिनों में केवल एक बार प्रवेश की अनुमति के लिये "लॉटरी-व्यवस्था" शुरु कर दी गई थी। गिल्ड ने अपने इन दोनों पत्रों में लिखा है: "वरिष्ठ पत्रकार याद दिलाते हैं कि आपातकाल के दौरान भी, जिन पत्रकारों को प्रैस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो की मान्यता किन्हीं कारणवश नहीं मिल पाई थी, उन्हें भी संसद की कार्यवाही के कवरेज की सुविधा से वंचित नहीं किया गया था।

राष्ट्रदूत (एच.यू.एफ.) के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक सोमेश शर्मा द्वारा वतन प्रेस, सुधर्मा, एम.आई.रोड़, जयपुर एवं सुधर्मा-II, लालकोठी शॉपिंग सेंटर, टोंक रोड़, जयपुर से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक:- राजेश शर्मा । आर.एन.आई. नं. 3641/57, ई-मेल-rastrdut@gmail.com कोटा कार्यालय:-पलायथा हाउस, छत्रपति शिवाजी मार्ग, कोटा। फोन:2386031, 2386032, फैक्स:0744-2386033 बीकानेर कार्यालय:-कुंम्भाना हाउस, हनुमान हत्था, बीकानेर। फोन:2200660, फैक्स: 0151-2527371 उदयपुर कार्यालय:-आयड, मेन रोड आयड, उदयपुर। फोन: 2413092, 2418945, फैक्स: 0294-2410146 अजमेर कार्यालय:-घूघरा घाटी, जयपुर रोड,अजमेर। फोन: 2627612, फैक्स:0145-2624665 जालोर कार्यालय :- जी 1/63, इन्डस्ट्रीयल एरिया, फेस प्रथम, जालोर। फोन: 226422, 226423, फैक्स: 02973-226424 हिण्डौनसिटी कार्यालय :- जी -1-201, रीको औद्योगिक क्षेत्र, हिण्डौनसिटी। फोन: 230200, 230400, फैक्स: 07469-230600 चूरू कार्यालय: एच-150, रीको औद्योगिक क्षेत्र, चूरू, फोन: 256906, 256907, फैक्स:01562-256908